कितनी धनराशि राजसहायता के रूप में दी गई ; और

(ग) सरकार भविष्य में इस राशि को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अंतर अर्थात उपभोक्ता राजसहायता ; (ii) बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्य राजसहायता प्रदान करती है। खाद्य राजसहायता की राशि की मात्रा उठान, खाद्य स्टाक और भाड़ा, ब्याज प्रभारों आदि जैसे अन्य तथ्यों तथा खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य पर निर्भर करती है ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को अदा की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार थी :—

वर्ष	खाद्य राज-सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
1986-87 . .	2000
1987-88 . .	2000
1988-89 . .	2200

स्टाफ की संख्या में कमी करने, भारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, किराए के अलाभकारी और फालतू गोदामों को त्यागने आदि जैसे उपाय कर भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत को कम करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

खाद्य तिलहनों की पिराई की क्षमता

@*32क. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमल नी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष खाद्य तेलों के उत्पादन का एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन अपर्याप्त होने का कारण देश में तिलहनों की पिराई की क्षमता का कम होना तथा पिराई की मशीनरी आधुनिक न होना है ;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग का आधुनिकिकरण करने तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई प्रोत्साहन नहीं दिए जा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) उद्योग की समग्र पिराई क्षमता देश में तिलहनों के कुल उत्पादन को खपाने के लिए पर्याप्त है ।

(ग) सरकार ने तेल पिराई उद्योग को अपग्रेड करने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर कुछ उपकरण आयात करने की अनुमति दी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Loopholes and Flaws in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987

*33. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some Women's Organisations have brought to the notice of Government some loopholes and flaws in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987; and

@पूर्वत: तारांकित प्रश्न 74, 28 दिसम्बर, 1989 से स्थानान्तरित ।

(b) if so, whether Government propose to bring forward an amending Bill before Parliament with a view to removing all the flaws in the Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) Yes, Sir.

(b) This question is under consideration.

Setting up of Vishwa Hindi Vidyapeeth

*34. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 329 given in the Rajya Sabha on 9th August, 1989 and state:

(a) whether the matter regarding the setting up of Vishwa Hindi Vidyapeeth has since been examined by Government; and

(b) if so, what follow up action has been taken so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) and (b) In reply to Rajya Sabha Starred Question No. 329, it was stated that the matter would be examined keeping in view, *inter alia* the overall resource constraints. Such examination has been undertaken with particular reference to the concept of Zero-base budgeting. It has been decided that the proposal may not be taken up for implementation for the present.

Projects Pending for Environmental Clearance

*35. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a act that a number of projects of the country are pending with Government for environmental clearance;

(b) if so, what was the total number of such projects upto November, 1989 on which decision could not be taken; and

(c) what is the number of those projects out of these which had been under consideration for two or more years and on which final decision has yet to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SMT. MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) A total of 146 projects were awaiting decision for environmental clearance on 30th November, 1989.

(c) Thirty of these projects have been under consideration for two or more than two years.

Establishment of a Regional Centre for Research on Atmospheric Science in Orissa

*36. SHRI BASUDEB MOHARATRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what action Government have taken on the scheme submitted by the Orissa Government for establishment of a Regional Centre for Research in Atmospheric Science;

(b) if no action has been taken so far, by when the said scheme is likely to be cleared by the Central Government; and

(c) what is the estimated cost of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) There is no such proposal under the consideration of the Government.

(b) and (c) Do not arise.